



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 570]
No. 570]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 1, 1988/कार्तिक 10, 1910
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 1, 1988/KARTIKA 10, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1988

अधिसूचना

मा.का.नि. 1052(प्र):-केंद्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधि-
नियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में
यथाप्रवृत्त इसलें उल्लेख अधिसूची के स्वतन्त्र (1) में विनिर्दिष्ट अधि-
नियमितियों को, अनुसूची के स्वतन्त्र (2) में की संस्थानों प्रविष्टियों में
विनिर्दिष्ट उपाचारों के अंगीकार करने हुए, खंडीय संघ राज्य क्षेत्र को
विस्तारित करने हैं।

अनुसूची

अधिनियमित	उपाचार
(1)	(2)
1. पंजाब साधारण विधायक-कर (संगोष्ठन) अधिनियम, 1973 (1973 का पंजाब अधिनियम सं. 11)	1. धारा 2 में, "पंजाब साधारण विधायक-कर अधिनियम, 1948", शब्दों और अंकों के स्थान पर "खंडीय संघ राज्य क्षेत्र में यथा-

(1)

(2)

- प्रवृत्त पंजाब साधारण विधायक-कर
अधिनियम, 1948" शब्द और
अंक रखे जाएंगे।
2. पंजाब साधारण विधायक-कर दूसरा
(संगोष्ठन) अधिनियम, 1973
(1973 का पंजाब अधिनियम
सं. 29)
2. धारा 3 का लोप किया जाएगा।
धारा 2 में, "पंजाब साधारण
विधायक-कर अधिनियम, 1948"
शब्दों और अंकों के स्थान पर
"खंडीय संघ राज्य क्षेत्र में यथा-
प्रवृत्त पंजाब साधारण विधायक-
कर अधिनियम, 1948" शब्द
और अंक रखे जाएंगे।
3. पंजाब साधारण विधायक-कर
(संगोष्ठन और विधिसाम्यकरण)
अधिनियम, 1976 (1976
का पंजाब अधिनियम सं. 11)
1. धारा 1 में, उपधारा (2) का
लोप किया जाएगा।
2. धारा 2 में, "पंजाब साधारण
विधायक-कर अधिनियम, 1948"
शब्दों और अंकों के स्थान पर
"खंडीय संघ राज्य क्षेत्र में यथा-
प्रवृत्त पंजाब साधारण विधायक-कर

(1)	(2)	(1)	(2)
	<p>अधिनियम, 1948" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;</p> <p>(ii) "और सदैव हुआ समझा जाएगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।</p> <p>3. धारा 3 में, "और सदैव हुआ समझा जाएगा ।</p> <p>शब्दों का लोप किया जाएगा ।</p> <p>4. धारा 4 और धारा 5 का लोप किया जाएगा ।</p>		<p>"बंड़ीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा-प्रवृत्त पंजाब साधारण विक्रय-कर अधिनियम, 1948" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।</p> <p>3. धारा 5 में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्र-पति, द्वारा नियुक्त प्रशासक" शब्द रखे जाएंगे ।</p>
4. पंजाब साधारण विक्रय-कर (संशोधन और विधिमाम्यकरण) अधिनियम, 1978 (1978 का पंजाब अधिनियम सं० 2)	<p>1. धारा 1 में, उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।</p> <p>2. धारा 2 में, "पंजाब साधारण विक्रय-कर अधिनियम, 1948" शब्दों और अंकों के स्थान पर "बंड़ीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त पंजाब साधारण विक्रय-कर अधिनियम, 1948" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।</p> <p>3. धारा 3 में, (i) "अप्रैल, 1973 के पहले दिन" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "पंजाब साधारण विक्रय-कर (संशोधन और विधिमाम्यकरण) अधिनियम, 1978 के बंड़ीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को विस्तारित किए जाने की तारीख" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।</p> <p>(ii) "राज्य" शब्द के स्थान पर, जहां जहां वह आता है "बंड़ीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे ।</p> <p>4. धारा 5 में, "पंजाब साधारण विक्रय-कर (संशोधन और विधिमाम्यकरण) अधिनियम, 1978 के प्रारम्भ के पूर्व" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर जहां जहां वह आते हैं, "पंजाब साधारण विक्रय-कर (संशोधन और विधिमाम्यकरण) अधिनियम, 1978 के बंड़ीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के विस्तारण के पूर्व" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।</p> <p>5. धारा 8 और 9 का लोप किया जाएगा ।</p>	<p>बंड़ीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर यथाविस्तारित पंजाब साधारण विक्रय-कर (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का पंजाब अधिनियम सं० 14) ।</p> <p>पंजाब साधारण विक्रय-कर अधिनियम, 1948 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।</p> <p>भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में पंजाब राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमिन हो:-</p> <p>1. संक्षिप्त नाम:- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब साधारण विक्रय-कर (संशोधन) अधिनियम, 1973 है ।</p> <p>2. 1948 के पंजाब अधिनियम 66 की धारा 4 का संशोधन- बंड़ीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त पंजाब साधारण विक्रय-कर अधिनियम, 1948 की उपधारा (5) में :-</p> <p>(i) खंड (ख) में, "25,000 रुपये" अंकों और शब्द के स्थान पर, "40,000 रुपये" अंक और शब्द रखे जाएंगे; और</p> <p>(ii) खंड (घ) में, "40,000 रुपये" अंकों और शब्द के स्थान पर "1,00,000 रुपये" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।</p>	उपबन्ध-1
			उपबन्ध-2
		<p>बंड़ीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर यथाविस्तारित पंजाब साधारण विक्रय-कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का पंजाब अधिनियम सं० 29)</p>	
		<p>पंजाब साधारण विक्रय-कर अधिनियम, 1948 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।</p> <p>भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में पंजाब राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमिन हो :-</p> <p>9. संक्षिप्त नाम:- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब साधारण विक्रय-कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1973 है ।</p> <p>2. 1948 के पंजाब अधिनियम 66 में नई धारा 3क का अन्त-स्थापन :- बंड़ीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथाप्रवृत्त पंजाब साधारण विक्रय-कर अधिनियम, 1948 की धारा 5 के परान्त निम्नलिखित धारा अंत स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-</p> <p>"5क. प्रतिष्कित कर का उद्घाटन:- (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्योहानी को करायेय भावार्थ पर प्रतिष्कित कर जो उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय कर के दो प्रतिशत की दर से संग्रहित किया जाएगा, उद्घाटन और संग्रहित किया जाएगा ।</p>	
5. पंजाब साधारण विक्रय-कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का पंजाब अधिनियम सं० 28)	<p>1. धारा 1 में, उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।</p> <p>2. धारा 2 में, "पंजाब साधारण विक्रय-कर अधिनियम, 1948" शब्दों और अंकों के स्थान पर</p>		

परन्तु इस अधिनियम के अधीन वेय सकलित कर और अधिभार ऐसे माल की बाधत जिसे केन्द्रीय विशय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 द्वारा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व का घोषित किया गया है, उस अधिनियम की धारा 15 द्वारा नियत दर से अधिक नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, जहाँ तक हो सके, उपधारा (1) के अधीन उद्घाटनीय अतिरिक्त दर के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उद्घाटनीय कर के संबंध लागू होते हैं।

उपाबंध—3

चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को यथाविस्तारित पंजाब साधारण विक्रय-कर (संशोधन और विधिमाम्यकरण) अधिनियम, 1979 (1979 का पंजाब अधिनियम सं. 11)

पंजाब साधारण विक्रय-कर अधिनियम, 1948 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचाईसवें वर्ष में पंजाब राज्यविधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब साधारण विक्रय-कर (संशोधन और विधिमाम्यकरण) अधिनियम, 1978 है।

2. 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की धारा 5 का संशोधन :— चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त पंजाब साधारण विक्रय-कर अधिनियम, 1948 को (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 5 के पहले परन्तुक्त में, "विलास-वस्तुओं" शब्द का लोप किया जाएगा।

3. 1948 के पंजाब अधिनियम 46 से उपाबद्ध अनुसूची क का संशोधन :—मूल अधिनियम में उपाबद्ध अनुसूची क में "विलास-वस्तुएं" शब्द का लोप किया जाएगा।

उपाबंध—4

चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को यथा विस्तारित पंजाब साधारण विक्रय-कर (संशोधन और विधिमाम्यकरण) अधिनियम, 1978 (1978 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 2)

पंजाब साधारण विक्रय-कर अधिनियम, 1948 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनतीसवें वर्ष में पंजाब राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब साधारण विक्रय-कर (संशोधन और विधिमाम्यकरण) अधिनियम, 1978 है।

2. 1948 के पंजाब अधिनियम 46 का संशोधन :—चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त पंजाब साधारण विक्रय-कर अधिनियम, 1948 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) "सामान्य उत्पादमूलक और कराधान अधिकारी" शब्दों के स्थान पर जहाँ जहाँ वे आते हैं, "उत्पादमूलक और कराधान अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

3. 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की धारा 5 का संशोधन :— मूल अधिनियम की उपधारा 5 की उपधारा (1-क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1-ख) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को पंजाब साधारण विक्रय-कर (संशोधन और विधिमाम्यकरण) अधिनियम, 1978 के विस्तारण की तारीख से ही उपधारा (1) के अधीन मारगरीन पर कर उसके विक्रय के पहले प्रक्रम पर उद्घाटित किया जाएगा जो प्रक्रम,—

(क) ऐसे व्योहारी को वषा में जो चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र से बाहर के किसी स्थान से चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में मारगरीन लाता है, विक्रय का यह प्रक्रम होगा जब ऐसा व्योहारी चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के भीतर पहली बार मारगरीन का विक्रय करता है;

(ख) ऐसे व्योहारी को वषा में जो चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के भीतर मारगरीन का विनिर्माण करता है, विक्रय का यह प्रक्रम होगा जब ऐसा व्योहारी चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में पहली बार मारगरीन का विक्रय करता है,

(ग) किसी अन्य व्योहारी को वषा में जिसने पूर्ववर्ती खण्ड में निविष्ट व्योहारी से मारगरीन का क्रय नहीं किया है, वह प्रक्रम होगा जिस पर ऐसा व्योहारी चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में पहली बार मारगरीन का विक्रय करता है;

परन्तु पश्चात्पूर्वी प्रक्रम पर मारगरीन के किसी विक्रय को इस अधिनियम के अधीन कर से तब तक छूट प्राप्त नहीं होगी जब तक कि ऐसे पश्चात्पूर्वी प्रक्रम पर विक्रय करने वाला व्योहारी विहित प्रत्य और रीति में उस रजिस्ट्रीकृत व्योहारी द्वारा जिससे मारगरीन क्रय को गई थी, सम्पत्तः भरा गया और हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं कर देता है।"

4. 1948 के पंजाब अधिनियम, 46 की धारा 10 का संशोधन :— मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (4) में "जिला उत्पादमूलक और कराधान अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "जिला उत्पादमूलक और कराधान अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

5. 1948 के पंजाब अधिनियम में नई धारा 11ककक का अन्तःस्थापन—मूल अधिनियम की धारा 11ककक के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

"11कककक. मारगरीन पर कर के कुछ निर्धारणों का पुनर्विचिन्तन और कुछ निर्धारणों का विधिमाम्यकरण—

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होने हुए जो निर्धारण प्राधिकारी चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को पंजाब साधारण विक्रय-कर (संशोधन और विधिमाम्यकरण) अधिनियम 1978 के विस्तारण के पूर्व किए गए ऐसे निर्धारणों पुनः निर्धारणों का जो पूर्वोक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं है पुनर्विचिन्तन करेगा और पहले किए गए आदेश का केटकार या पुनर्विचिन्तन करने वाला ऐसा आदेश करेगा जो पहले किए गए आदेश को पूर्वोक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक हो :—

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस धारा के अधीन किसी व्योहारी के विषय उसका सुनवाई के अवसर पर नहीं किया जाएगा।

(2) किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के तत्प्रतिफल किसी निर्णय जिम्मे या आदेश में किसी बात के होने हुए भी किन्तु उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को पंजाब साधारण विक्रय-कर (संगोषित और विधिसाम्यकरण) अधिनियम 1978 के विस्तारण के पूर्व इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मार्गरीन की बाबत किया गया या किए जाने के लिए सात्वित किसी कर का कोई निर्धारण पुनः निर्धारण उद्ग्रहण या संग्रहण या संरक्षण या निर्धारण पुनः निर्धारण उद्ग्रहण या संग्रहण के संबंध में की गई या की जाने के लिए सात्वित कोई कार्रवाई या बात उत्पत्ती हो विधिवत और प्रभावी होगी मानो ऐसे निर्धारण पुनः निर्धारण उद्ग्रहण या संग्रहण या कार्रवाई या बात पंजाब साधारण विक्रय-कर (संगोषित और विधिसाम्यकरण) अधिनियम 1978 द्वारा यथा संगोषित इस अधिनियम के अधीन की गई थी।

(3) संवेहों को दूर करने के लिए यह घोषित कि जाता है कि उपधारा (2) को किसी बात का यह प्रभाव नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी व्यक्ति को—

(क) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी अवधि के लिए मार्गरीन पर कर के निर्धारण पुनः निर्धारण उद्ग्रहण या संग्रहण को प्रभावित करने से या

(ख) पंजाब साधारण विक्रय-कर (संगोषित और विधिसाम्यकरण) अधिनियम 1978 द्वारा यथा संगोषित अधिनियम के अधीन उससे शोध्य रकम से अधिक उसके द्वारा संवत् किसी कर के प्रतिदाय का खदेबा करने से निवारित करने से।

6. 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की धारा 14-ख का संगोषित :— मूल अधिनियम की धारा 14-ख की उपधारा (6) के प्रत्युक्त में "जिजा का उत्पादशुल्क और कर अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "जिजा का भारसाधक सहायक उत्पादशुल्क और कराधान आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे।

7. 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की धारा 23 का संगोषित : मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) "उत्पादशुल्क और कराधान अधिकारी के रक का शब्दों के स्थान पर उत्पादशुल्क और कराधान अधिकारी से अनिश्चय रक का" शब्द रखे जाएंगे।

उपाबंध—5

चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को यथा विस्तारित पंजाब साधारण विक्रय-कर (संगोषित और विधिसाम्यकरण) अधिनियम, 1978 (1978 का पंजाब अधिनियम संख्या 26)

पंजाब साधारण विक्रय-कर अधिनियम, 1948 का संगोषित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उत्तरीसहस्र वर्ष में पंजाब राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब साधारण विक्रय-कर (उत्तरीय संगोषित) अधिनियम, 1978 है।

(2) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को यथा विस्तारित पंजाब साधारण विक्रय-कर अधिनियम, 1948 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 11 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(7) इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर, शारित या ब्याज की रकम का व्योहारी द्वारा उस तारीख तक की निर्धारण

प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, विहित रीति में संदाय किया जाएगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख ऐसी सूचना की तारीख की तारीख से पन्द्रह दिन से अल्प और तीस दिन से अधिक नहीं होगी :

परन्तु निर्धारण प्राधिकारी, जिसे के भारसाधक सहायक उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त से पूर्वनिर्धारित से ऐसे संदाय की तारीख को बड़ा संकेता या ऐसे संदाय की समुचित प्रतिभूति या बैंक प्रत्याभूति पर किसी द्वारा अनुज्ञात कर सकेगा।

3. 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की धारा II-ख का संगोषित : मूल अधिनियम की धारा II-ख में "अधिनोपित शास्ति" और "इस अधिनियम के अधीन" शब्दों के बीच से "या देय ब्याज" शब्दों का लोप किया जाएगा।

4. 1948 के पंजाब अधिनियम 46 में नई धारा II-घ का अन्तःस्थापन : धारा II-घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"II-घ (1) ब्याज या संदाय : यदि कोई व्योहारी धारा 10 की उपधारा (4) की अपेक्षासूत्र उससे शोध्य कर की रकम का संदाय करने में असफल रहेगा तो वह कर की रकम को प्रतिरिक्त उससे शोध्य कर की रकम पर, उप धारा की उपधारा (3) के विवरणी के प्रस्तुत किए जाने के अन्तिम तारीख के ठीक बाद की तारीख से 1 प्रतिशत प्रतिमास की दर पर, एक मास की अवधि के लिए और तत्पश्चात् डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर से, व्यक्तिक्रम ब्याज रहने तक, कर की रकम पर साधारण ब्याज का संदाय करने का बायी होगा।

(2) यदि मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर व्योहारी द्वारा देय कर या शास्ति की रकम का संदाय नहीं किया जाता है या, यदि ऐसी कोई अवधि विनिर्दिष्ट नहीं की जाती है, वहाँ ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर संदाय नहीं किया जाता है तो व्योहारी, कर या शास्ति की रकम के प्रतिरिक्त, उप तारीख के ठीक बाद की तारीख से जिस पर यथास्थिति, सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि या तीस दिन की अवधि समाप्त होती है, एक प्रतिशत प्रतिमास की दर पर, एक मास की अवधि के लिए और तत्पश्चात् डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर से, व्यक्तिक्रम ब्याज रहने तक, कर की रकम पर साधारण ब्याज का संदाय करने का बायी होगा।

परन्तु जहाँ किसी कर या शास्ति की ब्यूरी किसी न्यायालय के आदेश द्वारा स्थगित कर दी जाती है, यहाँ कर या शास्ति की रकम स्वगत आदेश रद्द कर दिए जाने के पश्चात् उस रकम पर जो अन्ततः देय पायी जाती है, पूर्वोक्त दर पर ब्याज सहित अयुक्त होगी और ऐसा ब्याज उस तारीख से जिसकी कर या शास्ति पहली बार देय होती है, संश्लेष होगी।

(3) इस धारा के अधीन संश्लेष ब्याज की रकम :—

(i) किसी मास के आग को एक मास और मी रूप से कम रकम की मी रूप मानकर संगणित की जाएगी;

(ii) संग्रहण जीव ब्यूरी के प्रयोक्तों के लिए, इस अधिनियम के अधीन कर समझा जाएगी;

(iii) इस अधिनियम के अधीन अधिनोपित शास्ति, यदि कोई हो, के प्रतिरिक्त होगी।

स्पष्टीकरण :—यदि कर की रकम का कोई संदाय किसी व्योहारी द्वारा बैंक से किया जाता है और उसका संबंधित बैंक द्वारा अन्ततः कर दिया जाता है तो वह उस व्योहारी की ओर से कर की रकम का संदाय करने में असफल रहने की ओर से आयेगा।

5. 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की धारा 12 का प्रतिस्थापन मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर निम्नलिखित द्वारा रखी जाएगी अर्थात् :—

“12-(1) प्रतिदाय :—निर्धारण प्राधिकारी विहित रीति में इस निमित्त आवेदन करने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत व्योहारी को उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदत्त किसी कर, ब्याज या शास्ति की रकम का प्रतिदाय तब करेगा;

(क) यदि इस प्रकार संदत्त कर, शास्ति या ब्याज की रकम इस अधिनियम के अधीन उससे शोध्य रकम से अधिक है, या

(ख) यदि इस प्रकार संदत्त कर की रकम किसी घोषित माल के विक्रय या क्रेय की वाबत है और ऐसा माल या तो प्रतिदाय बाउचर द्वारा या किसी अन्य अवधि की वाबत व्योहारी से शोध्य रकम के साथ इस प्रकार संदत्त रकम का समायोजन करके व्योहारी के विकल्प पर, अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रीत किया जाता है ;

परन्तु खण्ड (ख) के अधीन प्रतिदाय ऐसी शर्तों के जो विहित की जाए, अधीन होगा;

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कोई प्रतिदाय तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिदाय के लिए दावा उस तारीख से जिसको ऐसा दावा प्रतिभूत होता है, तीन वर्ष की अवधि के भीतर न किया गया होगा।

स्पष्टीकरण :—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में” पद का वही अर्थ होगा जो इसे केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 3 में समनुदेशित है।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, निर्धारण प्राधिकारी सर्वप्रथम प्रतिदाय की जाने वाली रकम को ऐसे समायोजन की तारीख पर व्योहारी से देय किसी रकम की वसूली के मद्दे सामयोजित करेगा और तत्पश्चात् प्रतिशेष, यदि कोई हो, का प्रतिदाय करेगा।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के आधार पर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को प्रतिदाय किए जाने के लिए अपेक्षित किसी रकम के आदेश की तारीख के नब्बे दिन के भीतर उसे प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो व्योहारी उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख की ठीक अगली तारीख से एक प्रतिशत प्रतिमास की दर से, एक मास के लिए और तत्पश्चात् प्रतिदाय किए जाने तक डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर पर ऐसी रकम पर साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा ;

परन्तु ब्याज की संगणना के प्रयोजन के लिए, किसी मास के आग की एक मास माना जाएगा और सौ रुपए से कम रकम को सौ रुपए माना जाएगा।

(4) यदि नब्बे दिन की पूर्वोक्त अवधि के भीतर प्रतिदाय अनुज्ञात करने में विवश ऐसे कारण से है जो निर्धारण प्राधिकारी के नियंत्रण से परे है या जो पूर्णतः या भागतः व्योहारी द्वारा किया गया माना जा सकता है, वहां ऐसे विलंब की अवधि को उस अवधि से अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके लिए ब्याज संदाय है।

(5) यदि इस बारत में कोई प्रश्न पैदा होता है कि क्या कोई अवधि उपधारा (4) के अधीन ब्याज की संगणना के प्रयोजनों के लिए अपवर्जित किया जाता है तो यह प्रश्न आयुक्त या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाएगा जो संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करें, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(6) जहां प्रतिदाय अनुज्ञात करने वाला आदेश किसी अपील या अग्रिम कार्यवाहियों की सामग्री है या जहां इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियां लंबित हैं और निर्धारण प्राधिकारी की यह राय है कि प्रतिदाय से वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, वहां निर्धारण प्राधिकारी प्रतिदाय को विधार्जित कर सकेगा और मामले की आयुक्त निर्देशित करेगा जिसके आदेश अन्तिम हों।

(7) वह अवधि जिसके दौरान प्रतिदाय उपधारा (6) के अधीन विधार्जित रहेगा इस धारा के अधीन ब्याज की संगणना के प्रयोजन के लिए अपवर्जित कर दी जाएगी।

6. 1948 के पंजाब अधिनियम, 46 की धारा 13 को संशोधन,— मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में, “दस रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पच्चीस रुपए” शब्द रख जाएंगे।

7. 1948 के पंजाब अधिनियम, 46 की धारा 27 का संशोधन,— मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ii) कर, शास्ति या ब्याज के संदाय की रीति।”।

[फा. सं. यू-11015/6/88-यू.टी.एल.]

अशोक नाथ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 1st Nov., 1988

NOTIFICATION

G.S.R. 1052 (E):—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to Union territory of Chandigarh, the enactments specified in column (1) of the Schedule hereto annexed, as in force in the State of Punjab at the date of this notification, subject to the modifications specified in the corresponding entries in column (2) of the Schedule.

THE SCHEDULE

Enactment	Modifications
(1)	(2)
1. The Punjab General Sales Tax (Amendment) Act, 1973 (Punjab Act No. 14 of 1973).	1. In section 2 for the words and figures “the Punjab General Sales Tax Act, 1948”, the words and figures “the Punjab General Sales Tax Act, 1946, as in force in the Union territory of Chandigarh,” shall be substituted.
	2. Section 3 shall be omitted.
2. The Punjab General Sales Tax (Second Amendment) Act, 1973 (Punjab Act No. 29 of 1973).	In section 2, for the words and figure “the Punjab General Sales Tax Act, 1948”, the words and figures “the Punjab General Sales Tax Act, 1948, as in force in the Union territory of Chandigarh,” shall be substituted.

1	2	1	3
3. The Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1976 (Punjab Act No. 11 of 1976).	<p>1. In section 1, sub-section (2) shall be omitted.</p> <p>2. In section 2,—</p> <p>(i) for the words and figures "the Punjab General Sales Tax Act, 1948", the words and figures "the Punjab General Sales Tax Act, 1948, as in force in the Union territory of Chandigarh," shall be substituted; and</p> <p>(ii) the words "and shall always be deemed to have been" shall be omitted.</p> <p>3. In section 3, the words "and shall always be deemed to have been" shall be omitted.</p> <p>4. Sections 4 and 5 shall be omitted.</p>		<p>(Amendment and Validation) Act, 1978 to the Union territory of Chandigarh" shall be substituted.</p> <p>5. Sections 8 and 9 shall be omitted.</p>
4. The Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1978 (Punjab Act No. 2 of 1978).	<p>1. In section 1, sub-section (2) shall be omitted.</p> <p>2. In section 2, for the words and figures "the Punjab General Sales Tax Act, 1948", the words and figures "the Punjab General Sales Tax Act 1948, as in force in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted.</p> <p>3. In section 3,—</p> <p>(i) for the words and figures "the 1st day of April, 1973," the words and figures "the date of extension of the Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1978 to the Union territory of Chandigarh," shall be substituted; and</p> <p>(ii) for the word "State" wherever it occurs, the words "Union territory of Chandigarh" shall be substituted.</p> <p>4. In section 5, for the words, brackets and figures "before the commencement of the Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1978" wherever they occur, the words, brackets and figures "before the extension of the Punjab General Sales Tax</p>	<p>5. The Punjab General Sales Tax (Second Amendment) Act, 1978 (Punjab Act No. 26 of 1978)</p>	<p>1. In section 1, sub-section (2) shall be omitted.</p> <p>2. In section 2, for the words and figures "the Punjab General Sales Tax Act, 1948", the words and figures "the Punjab General Sales Tax Act, 1948, as in force in the Union territory of Chandigarh be" shall, substituted.</p> <p>3. In section 5, for the words "State Government", the words "Administrator appointed by President under article 239 of the Constitution" shall be substituted.</p> <p>4. Section 8 shall be omitted.</p>

ANNEXURE-I

THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (AMENDMENT) ACT, 1973 (PUNJAB ACT NO. 14 OF 1973) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

An Act to amend the Punjab General Sales Tax Act, 1948.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Twenty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Punjab General Sales Tax (Amendment) Act, 1973.

2. Amendment of section 4 of Punjab Act XLVI of 1948.—In the Punjab General Sales Tax Act, 1948, as in force in the Union Territory of Chandigarh, in section 4, in sub-section (5),—

(i) in clause (bb), for the figure and word "25,000 rupees" the figure and word "40,000 rupees" shall be substituted; and

(ii) in clause (d), for the figure and word "40,000 rupees" the figure and word "1,00,000 rupees" shall be substituted.

ANNEXURE-II

THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 1973 (PUNJAB ACT NO. 29 OF 1973) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

An Act to amend the Punjab General Sales Tax Act, 1948.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Twenty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Punjab General Sales Tax (Second Amendment) Act, 1973.

2. Insertion of new section 5A in Punjab Act XLVI of 1948.—In the Punjab General Sales Tax Act, 1948, as in force in the Union Territory of Chandigarh, after section 5, the following section shall be inserted namely :—

"5A Levy of additional Tax.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be levied and collected on the taxable turnover of a dealer, an additional tax which shall be calculated at the rate of two per centum of the tax payable by him under this Act :

Provided that the aggregate of the tax and surcharge payable under this Act, shall not exceed in respect of goods declared to be of special importance in inter-State trade or commerce by section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956, the rate fixed by section 15 of that Act.

(2) Except as otherwise provided in sub-section (1), the provisions of this Act shall, so far as may be, apply in relation to the additional tax leviable under sub-section (1) as they apply in relation to the tax leviable under any other provision of this Act".

ANNEXURE-III

THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 1976 (PUNJAB ACT NO. 11 OF 1976) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

An Act to amend the Punjab General Sales Tax Act, 1948.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1976.

2. Amendment of section 5 of Punjab Act 46 of 1948.—In section 5 of the Punjab General Sales Tax Act, 1948, as in force in the Union Territory of Chandigarh (hereinafter referred to as the principal Act), in the first proviso, the word "luxury" shall be omitted.

3. Amendment of Schedule A appended to Punjab Act 46 of 1948.—In Schedule A appended to the principal Act, the word "LUXURY" shall be omitted.

ANNEXURE-IV

THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 1978 (PUNJAB ACT NO. 2 OF 1978) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

An Act to amend the Punjab General Sales Tax Act, 1948.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1978.

2. Amendment of Punjab Act 46 of 1948.—In the Punjab General Sales Act, 1948, as in force in the Union Territory of Chandigarh, (hereinafter referred to as the principal Act), for the words "Assistant Excise and Taxation Officer" wherever occurring the words "Excise and Taxation Officer" shall be substituted.

3. Amendment of section 5 of Punjab Act 46 of 1948.—In section 5 of the principal Act, after sub-section (1A), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(1-B) On and with effect from the date of extension of the Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1978 to the Union Territory of Chandigarh, tax on margarine under sub-section

(1) shall be levied at the first stage of sale thereof which stage shall,—

(a) in the case of a dealer who brings into the Union Territory of Chandigarh margarine from any place outside the Union Territory of Chandigarh, be the stage of sale when such dealer sells margarine in the first time within the Union Territory of Chandigarh;

(b) in the case of a dealer who manufactures margarine within the Union Territory of Chandigarh be the stage of sale when such dealer sells margarine for the first time in the Union Territory of Chandigarh; and

(c) in the case of any other dealer who has not purchased margarine from the dealer referred to in the preceding clause, be the stage at which such dealer sells margarine for the first time in the Union Territory of Chandigarh ;

Provided that no sale of margarine at a subsequent stage shall be exempted from tax under this Act unless the dealer effecting the sale at such subsequent stage furnishes to the assessing authority in the prescribed form and manner a certificate duly filled and signed by the registered dealer, from whom the margarine was purchased."

4. Amendment of section 10 of Punjab Act 46 of 1948.—In section 10 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "District Excise and Taxation Officer", the words "District Excise and Taxation Office" shall be substituted.

5. Insertion of new section 11-AAAA in Punjab Act, 46 of 1948.—After section 11-AAA of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

"11.AAAA Review of certain assessments of tax on margarine and validation of certain assessments.—

(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the assessing authority shall review such assessments, reassessments made before the extension of the Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1978 to the Union Territory of Chandigarh, as are not in conformity with the Provisions of this Act as amended by the aforesaid aforesaid Act; and make such order varying or revising the order previously made as may be necessary for bringing the order previously made into conformity with the provisions of this Act as amended by the aforesaid Act :

Provided that no order shall be made under this section against any dealer without giving him an opportunity of being heard.

(2) Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court or other authority to the contrary but subject to the provisions of sub-section (1), any assessment, reassessment, levy or collection of any tax in respect of margarine made or purporting to have been made, and any action or thing taken or done or purporting to have been taken or done in relation to such assessment, reassessment, levy or collection under the provisions of this Act before the extension of the Punjab General Sales Tax Amendment and Validation) Act, 1978 to the Union Territory of Chandigarh, shall be as valid and effective as if such assessment, reassessment, levy or collection or action or thing had been made, taken or done under this Act as amended by the Punjab Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1978..

(3) For the removal of doubts it is hereby declared that nothing in sub-section (2) shall be construed as preventing any person—

(a) from questioning in accordance with the provisions of the Act and Rules made thereunder, the assessment, reassessment, levy or collection of tax on margarine for any period, or

- (b) from claiming refund of any tax paid by him in excess of the amount due from him under the Act as amended by the Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1978.”

6. Amendment of section 14-B of Punjab Act, 46 of 1948.—In section 14-B of the principal Act, in the proviso to sub-section (6), for the words “Excise and Taxation Officer of the district”, the words “Assistant Excise and Taxation Commissioner in-charge of the district” shall be substituted.

7. Amendment of section 23 of Punjab Act 46 of 1948.—In section 23 of the principal Act, in sub-section (2), for the words “of the rank of Excise and Taxation Officer”, the words “not below the rank of Assistant Excise and Taxation Officer” shall be substituted.

ANNEXURE-V

THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 1978 (PUNJAB ACT NO 26 OF 1978) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

An Act to amend the Punjab General Sales Tax Act, 1948.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Punjab General Sales Tax (Second Amendment) Act, 1978.

2. In the Punjab General Sales Tax Act, 1948, as extended to the Union Territory of Chandigarh (hereinafter referred to as the principal Act), in section 11, for sub-section (7), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(7) The amount of any tax, penalty or interest payable under this Act shall be paid by the dealer in the manner prescribed by such date as may be specified in the notice issued by the assessing authority for the purpose and the date so specified shall not be less than fifteen days and not more than thirty days from the date of service of such notice :

Provided that the assessing authority may, with the prior approval of the Assistant Excise and Taxation Commissioner, in-charge of the district, extend the date of such payment or allow payment by instalments against an adequate security or Bank guarantee.”.

3. Amendment of section 11-B of Punjab Act 46 of 1948.—In the principal Act, in section 11B, between the words “penalty imposed” and “under this Act” the words “or interest payable” shall be inserted.

4. Insertion of new section 11-D in Punjab Act, 46 of 1948.—After section 11-C, the following section shall be inserted, namely:—

“11-D Payment of Interest.—(1) If any dealer fails to pay the amount of tax due from him as required by sub-section (4) of section 10, he shall, in addition to the amount of tax, be liable to pay simple interest on the amount of tax due from him at the rate of one per centum per month from the date immediately following the last date for the submission of the return under sub-section (3) of that section, for a period of one month and thereafter at the rate of one and a half per centum per month till the default continues.

(2) If the amount of tax or penalty due from a dealer is not paid by him within the period specified in the notice of demand or, if no period is specified, within thirty days from the service of such notice, the dealer shall in addition to the amount of tax or penalty, be liable to pay simple interest on such amount at the rate of one per centum per month from the date immediately following the date on

which the period specified in the notice or the period of thirty days, as the case may be, expires, for a period of one month and thereafter at the rate of one and a half per centum per month till the default continues :

Provided that where the recovery of any tax or penalty is stayed by an order of any court, the amount of tax or penalty shall, after the order of stay is vacated, be recoverable along with interest at the aforesaid rate on the amount ultimately found to be due and such interest shall be payable from the date the tax or penalty first became due.

(3) The amount of interest payable under this section shall—

- (i) be calculated by considering part of a month as one month and any amount less than one hundred rupees as one hundred rupees;
- (ii) for the purposes of collection and recovery, be deemed to be tax under this Act ;
- (iii) be in addition to the penalty, if any, imposed under this Act.”.

Explanation.—If payment of the amount of tax is made by any dealer through cheque and the same is dishonoured by the bank concerned it will amount to failure on the part of the dealer to pay the amount of tax.

5. Substitution of section 12 of Punjab Act 46 of 1948.—In the principal Act, for section 12, the following section shall be substituted, namely :—

“12 Refund.—(1) The assessing authority shall in the prescribed manner refund to a registered dealer applying in this behalf any amount of tax, interest or penalty paid by such dealer under this Act,—

- (a) if the amount of tax, penalty or interest so paid is in excess of the amount due from him under this Act; or
- (b) if the amount of tax so paid is in respect of the sale or purchase of any declared goods and such goods are sold in the course of inter-state trade or commerce, either by a refund voucher or, at the option of the dealer by adjustment of the amount so paid with the amount due from him in respect of any other period ;

Provided that the refund under clause (b) shall be subject to such conditions, as may be prescribed:

Provided further that no refund under this section shall be allowed unless the claim for refund is made within a period of three years from the date on which such claim accrues.

Explanation.—For the purposes of this sub-section the expression “in the course of inter-State trade or commerce” shall have the meaning assigned to it by section 3 of the Central Sales Tax Act, 1956.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the assessing authority shall first adjust the amount to be refunded towards the recovery of any amount due from the dealer on the date of such adjustment, and shall thereafter refund the balance, if any.

(3) Where any amount required to be refunded by the assessing authority to any person by virtue of an order issued under this Act is not refunded to him within ninety days of the date of the order, the dealer shall be entitled to get simple interest on such amount at the rate of one per centum per month from the date immediately following the date of expiry of the said period for a period of one month and hereafter at the rate of one and a half per centum per month till the refund is made: Provided that for the purpose of calculation of the interest, part of a month shall be considered as one month and any amount less than one hundred rupees shall be considered as one hundred rupees.

- (4) If the delay in allowing refund within the aforesaid period of ninety days is for reasons beyond the control of the assessing authority or attributable to the dealer, whether wholly or in part, the period of such delay shall be excluded from the period for which interest is payable.
- (5) If any question arises whether any period is to be excluded for the purposes of calculation of interests under sub-section (4) the same shall be referred to the Commissioner or such other officer as the Administrator appointed by the President under article 239 of the Constitution may, by notification, appoint, whose decision shall be final.
- (6) Where an order allowing refund is the subject matter of an appeal or further proceedings or where any other proceedings under this Act are pending, and the assessing authority is of the opinion

that the refund is likely to adversely affect the recovery, the assessing authority may withhold the refund and refer the case to the Commissioner whose orders shall be final.

- (7) The period during which the refund remains withheld under sub-section (6) shall be excluded for the purpose of calculation of interest under this section."

6. Amendment of section 13 of Punjab Act 46 of 1948.— In the principal Act, in section 13, in sub-section (2), in clause (a), for the words "ten rupees", the words "twenty-five rupees" shall be substituted.

7. Amendment of section 27 of Punjab Act 46 of 1948.— In the principal Act, in section 27, in sub-section (2), after clause (i), the following clause shall be inserted namely:—

- (ii) the manner of payment of tax, penalty or interest".

[No. U-11015/6/82-UTL]

ASHOK NATH, Jr, Secy.

